एनडीआरएफ के अधिकारियों के अनुसार 22 टीमों को पहले ही तैनात किया जा चुका है जबकि 28 टीमों को स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के भीतर अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि आसनी तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच चुका है।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 147 दिनांक:11-05-2022 बुधवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

नई दिल्ली में मंगलवार को संयुक्त हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार पर इसका नाम बदलकर विष्णु स्तम्भ करने की मांग की।

चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए NDRF की 50 टीमें तैनात

IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली । बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'आसनी' उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के करीब बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान 'आसनी' बुधवार की सुबह तक काकीनाडा और विशाखापत्तनम तटों के करीब पहुंच जाएगा और आंध्र प्रदेश तट के साथ आगे बढ़ेगा। इसके बाद यह धीरे-धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे चक्रवात आसनी के आज रात तक उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तरी आंध्र तट और उससे सटे ओडिशा तट तक पहुंचने की संभावना है।

चक्रवाती तूफान आसनी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (ऊ्ड) की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। एनडीआरएफ की कुल 50 टीमों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के अनुसार 22 टीमों को पहले ही तैनात किया जा चुका है, जबकि 28 टीमों को स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के भीतर अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि आसनी तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच चुका है।तैनात 22 टीमों में से 12 टीमों को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में नौ टीमों को तटीय आंध्र प्रदेश में और एक टीम को ओडिशा के बालासोर जिले में तैनात किया गया है।

तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ कर्मी चक्रवात के दौरान क्या करें और क्या न करें के बारे में तटीय इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और तट रेखा पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान/ आश्रयों में स्थानांतरित करने के लिए लोगों से खास अपील कर रहे हैं। मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आइएमडी इंटरनेट मीडिया का सहारा लेकर संदेशों के जरिए लोगों को तूफान की ताजा स्थिति से अवगत कर रहा है।

वहीं, भुवनेश्वर के मौसम विभाग ने यह भी बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान आसनी अगले 24 घंटों में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके प्रभाव में आने वाले मलकानगिरी, गजपति, गंजम, पुरी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है।

मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार बुधवार को उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश और तटीय ओडिशा में भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तटीय पश्चिम बंगाल के अलग-अलग स्थानों पर बारिश का अलर्ट है। 12 मई यानी गुरुवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और अलग-अलग स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है।

श्रीलंका में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश, खूनी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला

कोलंबो । भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने थलसेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या आम लोगों को चोट पहुंचाने वाले किसी भी दंगाई को गोली मारने का आदेश जारी किया है। यह आदेश राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा लोगों से हिंसा और बदले की भावना वाले कृत्य रोकने की अपील के बाद आया है।। श्रीलंका सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में तेज हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप विरोध स्थलों पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

सेना के प्रवक्ता ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों बलों को सार्वजनिक संपत्ति लूटने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है। देश में विरोध की पहचान हो गई है, जिन्होंने मंत्रियों और सांसद के घरों को जला दिया है।

सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के मोरातुवा मेयर समन लाल फर्नांडो और सांसद सनथ निशांत, रमेश पथिराना, महिपाल हेराथ, थिसा कुट्टियाराची और निमल लांजा के आधिकारिक आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और श्रीलंका के पोदुजाना पेरामुना के सांसदों पर हमला कर दिया।

डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यहां तक कि श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) के कुछ कार्यालयों को भी आग के हवाले कर दिया गया। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को हिंसक विरोध के बाद इस्तीफा देने के एक दिन बाद त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण देशव्यापी कर्फ्यू लगा।

प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के कोलंबो स्थित सरकारी आवास से निकलने के बाद त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में शरण ली। यह खबर फैलने के बाद मंगलवार को नौसैनिक अड्डे के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, प्रदर्शनकारी महिंदा को परिसर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों में राजपक्षे परिवार और सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ गुस्सा किस कदर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर चेकप्वाइंट स्थापित कर दिया है ताकि इस परिवार का कोई भी करीबी देश छोड़कर न भाग सके।

समाचार पत्र 'डेली मिरर' की खबर अनुसार, महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को पूरी रात भीड़ उनके सरकारी आवास 'टेंपल ट्रीज' में घुसने की कोशिश करती रही। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलंबो गजट की रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकाप्टरों को आज वीवीआईपी के साथ राजधानी शहर से निकलते देखा गया और कुछ ने अनुमान लगाया कि वे राजपक्षे परिवार के सदस्य थे। इससे पहले आज प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पश्चिमी प्रांत में मंगलवार को कोलंबो में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला किया।

पुलिस ने बताया कि कोलंबो में बीरा झील के पास सीनियर डीआईजी पर हमला हो गया। उन्होंने कहा कि समूह ने डीआईजी के वाहन को भी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने सोमवार को कहा कि वह प्रदर्शनकारियों द्वारा मंत्रियों के घरों को जलाने के बाद श्रीलंका में अस्थिर स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के राज्य विभाग ब्यूरो ने ट्वीट किया कि श्रीलंका में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और निर्दोष दर्शकों के खिलाफ हिंसा से बहुत चिंतित हैं। सभी श्रीलंकाई लोगों से देश की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के दीर्घकालिक समाधान खोजने और सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह कर रहे हैं।

इससे पहले सोमवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने हंबनटोटा शहर में राजपक्षे परिवार के पैतृक आवास को आग लगा दी और राजपक्षे बंधुओं के पिता के स्मारक को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कुरुनेगला स्थित महिंदा के आवास को भी आग के हवाले कर दिया था। साथ ही 14 पूर्व मंत्रियों और 18 सांसदों के आवासों व कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया था, जिनमें पूर्व डिप्टी स्पीकर और राजपक्षे परिवार के निष्ठावान नेता शामिल हैं।

पंडित शिव कुमार शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि

- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया

मुंबई, (ईएमएस)। मशहूर संतूर वादक और भारतीय संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया. वह 84 साल के थे. वह पिछले 6 महीने से किडनी संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. वह भारत के जानेमाने शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने फिल्मों में भी संगीत दिया था। उनके सचिव दिनेश ने बताया कि मुंबई के पाली हिल स्थित आवास पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे शर्मा का निधन हो गया। अगले सप्ताह उन्हें भोपाल में एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। उनके परिवार में पत्नी मनोरमा और बेटे राहुल तथा रोहित हैं। शर्मा के सचिव ने कहा कि पार्थिव शरीर को पाली हिल वाले घर में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शर्मा के पार्थिव शरीर को बुधवार को पूर्वाह्न 10 बजे जुहू स्थित अभिजीत कोआपरेटिव सोसाइटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां उसे दोपहर एक बजे तक जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शर्मा की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। बयान में कहा गया, ''पंडित शिवकुमार शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश दिए हैं।''

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों ने शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मोदी ने कहा, ''पंडित शिवकुमार शर्मा जी के निधन से हमारे सांस्कृतिक जगत की क्षति हुई है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संतूर को लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करता रहेगा। उनके साथ हुई बातचीत मुझे याद है। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

कुतुब मीनार के पास हिन्दू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा पाठ नाम बदलने की उठाई मांग

नई दिल्ली (ईएमएस)। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कुछ हिन्दू संगठनों के सदस्यों द्वारा ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इसके साथ ही हिन्दू संगठनों द्वारा इसका नाम कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, मंगलवाल सुबह से ही कुतुब मीनार के पास हिन्दू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध जताया। हालांकि, इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है।इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत एक सनातन भूमि है इसलिए कुतुब मीनार के साथ ही सभी मुगलकालीन इमारतों और सड़कों का नाम भी बदला जाना चाहिए। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भारत एक सनातन भूमि है इसलिए कुतुब मीनार के साथ ही सभी मुगलकालीन इमारतों और सड़कों का नाम भी बदला जाना चाहिए।

एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करेगी कांग्रेस, गांधी परिवार पर भी लागू होगा यह नियम

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देने, अहम पद पर रहने के बाद तीन साल कूलिंग ऑफ पीरियड होने और पैनलों में बड़ी संख्या को कम करने जैसे प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान को सुझाव दिया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल नेताओं को एक कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन सालों तक पद से दूर रखा जाना चाहिए।

इस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने पर भी सहमति बनी है। पार्टी का मानना है कि इससे वह भाजपा की ओर से लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों का जवाब दे सकेगी। उदयपुर में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। इसमें इन सभी प्रस्तावों को पेश किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी उन सभी पेचों को कस लेना चाहती है, जहां कोई भी ढिलाई नजर आ रही है।

इसी के तहत उसने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसके अलावा यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए भी प्लानिंग करने में जुटी है। यही नहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी पार्टी की नजर है, जहां इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। इस चिंतन शिविर में 400 पार्टी नेता शामिल होंगे।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद एक नेता ने कहा एक परिवार एक टिकट के प्रस्ताव पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ऐलान करेंगे। यह भी ऐलान किया जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव में परिवार का एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वाले नेता संसदीय बोर्ड के भी पुनर्गठन की बात करते रहे हैं। राजनीतिक मामलों की समिति ने सुझाव दिया है कि पार्टी को देश भर में गठबंधन करने चाहिए। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेना चाहिए। भूपिंदर सिंह हुड्डा की लीडरशिप में किसानों को लेकर बनी एक कमिटी ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। इनमें सबसे अहम सिफारिश यह है कि पार्टी ऐलान करे कि जब वह केंद्र की सत्ता में आएगी तो फिर किसानों के एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाएगा।

इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि एमएसपी से कम कीमत पर खुले बाजार में उत्पाद को खरीदने वाले लोगों को सजा दी जाएगी और ऐसा करना अपराध होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कुछ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए देश भर में राहुल गांधी का दौरा कराए जाने का भी सुझाव दिया। उनका सुझाव था कि राहुल गांधी को देश के सभी राज्यों की यात्रा करनी चाहिए ताकि पार्टी के वर्कर्स और नेताओं में उत्साह का संचार हो सके। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष और संगठन चुनावों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, अधिकारियों की गले में अटकी सांसें

10 दिन में दो बार आ चुकी है तकनीकि खराबी

पंतनगर, 10 मई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की आज मंगलवार को पंतनगर एयरपोर्ट में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। मौसम खराब होने की वजह से चॉपर की आपात लैंडिंग की गई है। धामी खटीमा से देहरादून वापस लौट रहे थे। वहीं 10 दिन में इस तरह की तकनीकी खराब दो बार आ चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से देहरादून वापस लौट रहे थे अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद अंधड़ और बारिश के बीच मौसम खराब होने पर पंतनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसम साफ होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 बजकर 40 मिनट पर देहरादून के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। वह यहां मौसम खराब होने के चलते पंतनगर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एनेक्सी प्रथम में विश्राम एवं भोजन के बाद वह प्राइवेट हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवान हुए। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जिला महामंत्री विवेक सक्सेना विकास शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। एसडीएम प्रत्यूष सिंह ने बताया कि आंधी और बारिश के चलते पंतनगर एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बाद में मौसम साफ हो गया था। कुछ देर में सीएम देहरादून को रवाना हो गए।

तिकुनिया हिंसा कांड: पुलिस कस्टडी में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मूंछों पर ताव देते पहुंचा कोर्ट

लखीमपुर खीरी (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की लखीमपुर खीरी जिला कोर्ट में हाजिरी के समय भी रुआब के अंदाज में दिखा। आशीष मिश्रा की ओर से जिला अदालत में आज डिस्चार्ज आवेदन डाला गया। इसके लिए जिला कोर्ट पहुंचा आशीष मिश्रा मीडिया के सामने मूंछों पर ताव देता दिखा। लखीमपुर खीरी में हुए पिछले साल हुए तिकुनिया हिंसाकांड के सभी 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में दायर हो चुकी है। माना जा रहा था कि कोर्ट में आशीष मिश्रा पर आरोप तय हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को तय की है।

मोहाली ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, रिंडा पर गहराया शक

मोहाली (ईएमएस)। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा पर ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस अभी तक हमलावरों का पता नहीं लगा पाई है, हालांकि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेनेड लगभग 100 मीटर के दायरे से फेंका गया था। एनआईए, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से मौके का दौरा किया है।

आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राज्य पुलिस कार्यालय पर हमले के लिए आरपीजी का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि आरपीजी या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल हथियार को कहते हैं। वैसे को इसका इस्तेमाल अक्सर टैंक विरोधी हथियारों के रूप में किया जाता है लेकिन पंजाब में इस तरह के हथियार का पहुंचना काफी चौंकाने वाला है।

पंजाब पुलिस का खुफिया दफ्तर ओपन है लेकिन कर्मचारियों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा ऐसा लगता है कि आरोपियों को विदेश से काम करने वाले लोगों ने काम पर रखा था। पुलिस विस्फोट में गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा की भूमिका की जांच कर रही है। बताया जाता है कि रिंडा पाकिस्तान में रहता है। वह फिरोजपुर-टू-तेलंगाना हथियार तस्करी मामले के अलावा नवांशहर पुलिस सीआईए कार्यालय विस्फोट मामले में वांछित है।

एक अधिकारी ने कहा, चिंता की बात यह है कि हमलावरों ने इस बार खुफिया मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत की है। यह परेशान करने वाला है कि आतंकी समूह इस तरह के काम को करने के लिए पैसे की पेशकश करके आसानी से युवाओं की भर्ती कर रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में हुए विस्फोट को राज्य की शांति भंग करने वाले लोगों की कायराना हरकत बताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलके हर हालत में शांति क़ायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा मोहाली में हुए ब्लास्ट की जांच पुलिस कर रही है। जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की उसे बख़्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित खुफिया विभाग के मुख्यालय पर सोमवार रात एक विस्फोट किया गया था। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है।

लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को दी सख्त चेतावनी,

मुंबई । मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को इस मामले में अपनी पार्टी के धैर्य की परीक्षा के खिलाफ आगाह किया है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि 28,000 से अधिक मनसे कार्यकर्ताओं को निवारक नोटिस दिए गए हैं, जबकि हजारों को राज्य से बाहर भेज दिया गया है।

उद्धव को लिखे पत्र में सवाल करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि यह (पुलिस कार्रवाई) किस लिए है? मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाने के लिए जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे हैं? साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि पुलिस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं की तलाश कर रही है जैसे कि वे पाकिस्तानी आतंकवादी या पूर्ववर्ती निजाम शासन के 'रजाकार' हों।

मनसे प्रमुख ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पुलिस ने आतंकवादियों या मस्जिदों में छिपे हथियारों का पता लगाने के लिए वही सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि मराठी लोग और हमारे हिंदू भाई राज्य सरकार के इस रुख को देख रहे हैं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि मेरे पास राज्य सरकार को बताने के लिए केवल एक ही चीज है। हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। शक्ति का ताम्रपत्र लेकर कोई नहीं आया है। आप भी नहीं।

बता दें कि राज ठाकरे ने इससे पहले 4 मई को राज्य सरकार को मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिदों के बाहर अधिक मात्रा में 'हनुमान चालीसा' बजाया जाएगा।

गौरतलब है कि राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर राज्य सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर नीति बनानी चाहिए। 4 मई को हनुमान चालीसा बजाने पर एक उद्दंड स्थिति बनाए रखते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक कि मस्जिदों के सभी साउंड सिस्टम को बंद नहीं कर दिया जाता है।

शिमला पुलिस मुख्यालय पर भी हो सकता है मोहाली जैसा हमला, मिली चेतावनी

शिमला(ईएमएस)। मोहाली पुलिस के खुफिया कार्यलयपर हमले के बाद खालिस्तानी सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भी चेताया है। खबर है कि एसएफजे ने चेतावनी दी है कि यह हमला शिमला पुलिस मुख्यालय पर भी हो सकता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे मिले थे। इसके बाद पुलिस ने जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पन्नू ने ऑडियो मैसेज से चेतावनी दी है, यह ग्रेनेड हमला शिमला पुलिस मुख्यालय पर भी हो सकता है। साथ ही एसएफजे ने सीएम ठाकुर को मोहाली हमले से सबक लेने की सलाह दी है। उसका कहना है कि सिख समुदाय को उकसाया नहीं जाना चाहिए।

गौरतलब है कि मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागी गई थी। हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मोहाली पुलिस के बयान के अनुसार, सेक्टर 77, एसएएस नगर में शाम करीब 7.45 बजे मामूली धमाका हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। धर्मशाला पुलिस ने पन्नू के खिलाफ धारा 153-ए और 153-बी, यूएपीए की धारा 13 समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। रविवार को धर्मशाला स्थित विधानसभा में खालिस्तानी झंडे मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके तुरंत बाद ही गेट और दीवारों से झंडे हटाए गए।

हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, एडीजीपी-सीआईडी, आईजी/जीआईजी रैंज और जिला पुलिस अधीक्षकों को सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करने और होटल, सराय आदि जैसे संभावित ठिकानों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्हें स्पेशल सिक्युरिटी यूनिट्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड्स, और क्विक रिएक्शन टीम को तैयार रखने और हाई अलर्ट पर रहने और डैम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहरों सरकारी भवनों और अहम स्थानों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं।'

6 सालों में राजद्रोह के 356 मामले दर्ज हुए, 12 पर ही सिद्ध हो पाया अपराध

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में राजद्रोह कानून को लेकर घमासान मचा है। कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने इस कानून को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यसभा में बहस कराने की मांग की थी। पवार ने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल लोगों की लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून को खत्म करने की मांग अक्सर उठती रही है। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए हलफनामा भी दायर किया है। इस कानून के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं।

एनसीआरबी के आंकड़ों को जानने से पहले, हम यह जान लें कि आखिर राजद्रोह का कानून है क्या? भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या किसी और तरह से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी है। राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है। इसमें सज़ा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2020 के दौरान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत 356 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, जिसमें करीब 548 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पिछले 6 सालों में 12 गिरफ्तार लोगों पर अपराध साबित भी हुआ। अगर साल के हिसाब से आंकड़ों को समझें तो राजद्रोह कानून के तहत 2020 में कुल 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं 2019 में यह आंकड़ा 99, 2018 में 56 था, इनकी तुलना में 2017 में सबसे ज्यादा कुल 228 जबकि 2016 में 48 और 2015 में 73 लोगों को हिरासत में लिया गया।

आईपीसी की धारा 124 ए के देश भर में 2020 में 73 मामले दर्ज हुए। वहीं 2019 में इसकी संख्या 93, 2018 में 70, 2017 में 51, 2016 में 35 और 2015 में 30 मामले दर्ज हुए। इस तरह से अगर आरोप सिद्ध होने पर नजर डालें तो जहां 2020 में 33.3 फीसद आरोप सिद्ध हुए वहीं 2019 में यह आंकड़ा 3.3 फीसद, 2018 में 15.4 फीसद, 2017 में 16.7 फीसद और 2016 में कुल 33.3 फीसद लोगों पर आरोप साबित हुआ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक अगर उम्र के हिसाब से 2015 से 2020 के आंकड़ों को देखें तो जो कुल 548 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें 290 यानी करीब 53 फीसद लोग 18-30 उम्र समूह में आते थे। वहीं 35 फीसद लोग 30-45 साल के दायरे में थे।

राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले (2018-19, 23 मामले और 2020 में 10 मामले) दर्ज हुए। वहीं 2018 में आंध्र प्रदेश में करीब 15 मामले, मध्य प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 3 मामले दर्ज हुए। इसी तरह 2019 में उत्तर प्रदेश में 9, नागालैंड में 11 और कर्नाटक में 18 मामले दर्ज हुए। 2020 में मणिपुर में राजद्रोह के 15 मामले सामने आए वहीं इसी साल असम में 12, कर्नाटक में 8, उत्तर प्रदेश में 7 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल गृह मंत्रालयआपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा से पहले सभी हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा कर रहा है।

कार्टून कोना

जन हितैषी

खालिस्तान की वापसी

कुछ वर्षों पहले तक लग रहा था कि खालिस्तान के नाम लेवा शायद अब नहीं बचे हैं और गिने-चुने जो स्वयंभू नेता विदेशों में रह रहे हैं, वे भी ठंडे पड़ चुके होंगे। लेकिन 2018 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारत के स्वतंत्रता दिवस से तीन दिन पहले खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने जो रैली निकाली, वह भारत के लिए गंभीर खतरे का संकेत था। इस रैली से तथाकथित खालिस्तान समर्थक नेताओं ने अपनी मौजूदगी का अहसास कराने की कोशिश की थी। इसके जरिए यह संदेश दिया गया था कि अलग राष्ट्र की मांग को लेकर खालिस्तान समर्थकों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब इस रैली का असर भारत में दिखने लगा है। हाल की घटनाओं को देखें तो कई में खालिस्तान का नाम सामने आया है। जजों को धमकी, करनाल में 4 आतंकियों का पकड़ा जाना, पटियाला में शिवसैनिकों के साथ झड़प या अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर झंडे लगाना, सारी कवायद अचानक हुई नहीं है। अगर ताजा घटनाक्रम को देखें तो रविवार सुबह धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार और चारदीवारी पर खालिस्तान के झंडे बंधे मिले थे। दोषियों ने विधानसभा परिसर के भीतरी इलाकों में पुलिस की तैनाती का फायदा उठाकर दीवारों और गेट पर झंडे लगा दिए। विधानसभा परिसर के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस तैनात हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। इसलिए पोस्टर को दीवार और विधानसभा के मुख्य द्वार पर लगाया गया। जांच में क्या सामने आएगा, यह बाद में पता चलेगा मगर अभी जिस तरह से इस तरह की हरकतें बढ़ी हैं, वह चिंता बढ़ाने वाली हैं। 1990 के दशक में पंजाब के सुपरकॉप केपीएस गिल ने सख्ती से निपटते हुए पंजाब को खालिस्तानी आतंकवादियों से मुक्ति दिलवाने में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन अब ये लोग फिर सिर उठाने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खालिस्तान की मांग को लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले बचे-खुचे नेता ऐसा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि ढाई दशक बाद फिर से खालिस्तान की मांग को जो हवा दी जा रही है, उसके पीछे आखिर कौन है? सिख फॉर जस्टिस को योजनाबद्ध तरीके से पाला-पोसा जा रहा है। मानवाधिकार संगठन होने का दावा करने वाले इस संगठन के साथ ब्रिटेन की वामपंथी ग्रीन पार्टी खड़ी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस पार्टी की एकमात्र निर्वाचित नेता कैरोलीन लुकास ने खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में यहां तक कहा था कि सिख लोगों को यह निर्धारित करने का हक है कि वे अपने लिए स्वतंत्र पंजाब चाहते हैं। जाहिर है, ब्रिटेन की धरती पर खालिस्तानी नेताओं की पौध तैयार करने का काम चल रहा है। योजना लंबी है कि कब क्या करना है। इससे लोगों के मन में फिर से यह बात बैठेगी कि सिखों का अलग देश खालिस्तान होना चाहिए। भारत ने करीब डेढ़ दशक तक पंजाब के आतंकवाद को झेला है और इसकी भारी कीमत चुकाई है। हजारों निर्दोष भारतीय नागरिक आतंकवादियों की हिंसा का शिकार हुए। अब इस दौर में खालिस्तान की मांग करने वालों की आवाज उस देश से आई है जो आतंकवाद के खात्मे में हर तरह से भारत के साथ होने का दावा करता रहा है और खुद भी इसके खतरों से दो-चार रहा है। सिख फॉर जस्टिस यूरोप के कई देशों में सक्रिय है। अमेरिका और कनाडा में इसके तार हैं। इस साल फरवरी में कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ खालिस्तान समर्थक जसपाल अटवाल के संपर्कों का खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अटवाल 1986 में पंजाब के एक मंत्री की हत्या में दोषी करार दिया गया था और अब कनाडा का नागरिक है। इस तरह की गतिविधियां जिस तेजी से सिर उठा रही हैं, उसे लेकर भारत सरकार को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत को उन देशों की सरकारों पर भी दबाव बनाना होगा जहां खालिस्तान के नाम पर आज भी गतिविधियां जारी हैं।

भाजपा का नया खेल

जम्मू-कश्मीरः सीटें बढ़ाकर कब्जे की जुगत....?

देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने ''चक्रवर्ती सम्राट'' अभियान की शुरूआत जम्मू-कश्मीर से करना चाहती है, उसे पता है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने की नाराजी अभी वहां के वोटरों से दूर नहीं हुई है, इसलिए अब इस राज्य के वोटरों को मनाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभाल लिया है, साथ ही चूंकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा का वर्चस्व है और कश्मीर में शून्य की स्थिति है, इसलिए हाल ही में परिसीमन की औपचारिकता के माध्यम में जम्मू क्षेत्र में विधानसभा सीटों के इजाफें के प्रयास किए गए और जम्मू क्षेत्र में आधा दर्जन नई विधानसभा सीटें बढ़ाकर जम्मू क्षेत्र की सीटें 43 तथा कश्मीर क्षेत्र में मात्र एक सीट की वृद्धि कर यहां सीटों की संख्या 47 कर दी गई है, अर्थात् अब इस राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 90 हो गई है।

अब यह तो स्वाभाविक है कि इस मशक्कत के बाद अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के लिए विधानसभा के चुनाव जरूरी है, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और कौशिश की जा रही है कि 6 महीनें बाद नवम्बर में गुजरात व हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव करवा दिये जाए और येन-केन-प्रकारेण अपने प्रमुख गढ़ जम्मू के बलबूते पर भाजपा वहां बहुमत प्राप्त कर ले और अपनी सरकार बना ले, इसलिए भाजपा के अभी से ये प्रयास शुरू हो गए है कि जम्मू क्षेत्र की 47 सीटों में से लगभग सभी सीटें भाजपा के कब्जें में हो और कश्मीर क्षेत्र में भी अपना झण्डा गाडने का सपना पूरा हो, इस तरह जम्मू आधारित बहुमत के बल पर भाजपा इस राज्य में अपनी सरकार गठित कर ले, इसलिए प्रधानमंत्री जी का रूझान इन दिनों कश्मीर की ओर अधिक ही है।

इधर यदि हम कश्मीर की बात करें तो वहां के राजनेताओं व आम नागरिकों की अनुच्छेद 370 खत्म करने की नाराजी बिल्कुल कम नहीं हुई है, इस एक मसले पर कश्मीर के सारे राजनेता व उनके राजनीतिक दल एक साथ है और एकजुट होकर भाजपा का विरोध कर रहे है, यद्यपि अपनी राजनीतिक चाल के तहत् भारतीय जनता पार्टी शासित केन्द्र सरकार ने परिसीमन आयोग के माध्यम से पहली बार कश्मीरी पण्डितों के लिए दो तथा अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित करने का प्रयास किया है, किंतु जहां तक कश्मीरी पण्डितों का सवाल है, उनकी भी भाजपा से जबरदस्त नाराजी है, क्योंकि 2014 के चुनावी घोषणा-पत्र में इनका दर्द शामिल करने के बावजूद आठ साल के अब तक के शासनकाल में भाजपा ने कश्मीरी पण्डितों का अपनी जन्म भूमि छोड़ने का दर्द दूर नहीं किया और वे अभी भी निर्वासित जिन्दगी जीने को मजबूर है। कुल मिलाकर भाजपा ने परिसीमन का नाटक करके जम्मू कश्मीर में सात विधानसभा सीटें बढ़वा दी है और इस राज्य में अब विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से 90 हो गई है। भाजपा को उम्मीद है कि यदि जम्मू संभाग की 43 सीटों में से 40 सीटें भी भाजपा कबाड़ लेती है तो तीन चार सीटों के लिए कश्मीर में मशक्कत कर इस राज्य में भाजपा सरकार बना सकती है। चूंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव गुजरात व हिमाचल प्रदेश के साथ प्रस्तावित होने जा रहे है और इसलिए चूंकि गुजरात-हिमाचल प्रदेश पर भाजपा का वर्चस्व पहले से ही है, इसलिए भाजपा पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पर ही केन्द्रीत करने वाली है और येन-केन-प्रकारेण वहां सरकार स्थापित करना चाहती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पिछले चार सालों (जून 2018) से जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है तथा यहां उप-राज्यपाल जी की ही केन्द्रीय नेतृत्व में सरकार चल रही है यह भी उल्लेखनीय है कि जिस परिसीमन का सहारा लेकर भाजपा ने यहां सीटों का इजाफा किया है, उसी तरह 1995 में यहां परिसीमन आयोग का गठन कर यहां आठ जिलों और नई तहसीलों का गठन किया था। अब परिसीमन आयोग ने यहां की पांच लोकसभा सीटों में प्रति लोकसभा 18 सीटों के आधार पर राज्य की 90 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया है।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि पांच अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा की सदस्य संख्या एक सौ ग्यारह थी, इनमें से 45 कश्मीर में, 37 जम्मू में और चार सीटें लद्दाख में थी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई है, अभी तक इस राज्य की 87 सीटों पर चुनाव होते आए है। अलग केन्द्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख की चार सीटों को हटा दिया गया है, इसलिए अब इस राज्य में विधानसभा की 83 सीटें है, जो अब सात सीटें बढ़ने से 90 सीटें हो जाएगी।

इस प्रकार कुल मिलाकर इस राज्य के राजनीतिक परिदृष्य की कल्पना की जाए तो छः माह बाद यहां होने वाला विधानसभा चुनाव जबरदस्त होगा, भाजपा जहां यहां अपनी सरकार के लिए एड़ी-चौटी का जोर लगाएगी, वहीं भाजपा के खिलाफ एक जुट हो रहे स्थानीय राजनीतिक दल व उनके नेता कश्मीरियों को अपने त्रासदी भरे पुराने दिनों की याद दिलाकर भाजपा के प्रति उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे है। अब यही दिलचस्प होगा कि इस 'रस्साकशी' में जीत किसकी होती है? (लेखक-ओमप्रकाश मेहता /ईएमएस)

हिन्दू राष्ट्र के नाम पर समाज विभाजक एजेण्डा?

भारत में सक्रिय हिंदूवादी संगठनों द्वारा कभी 'हिन्दू राष्ट्र' निर्माण तो कभी 'अखंड भारत' की संकल्पना प्रायः की जाती रही हैं। आज के ऐसे दौर में जब कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मंहगाई और बेरोज़गारी अपने चरमोत्कर्ष पर हो, इसी तरह के नारों से आम लोगों का ध्यान भटकाकर देश में बहुसंख्यवादी राजनीति की आड़ में सत्ता संरक्षण में एक बहुत बड़ा 'गिरोह ' सक्रिय हो कर लोगों को 'हिन्दू राष्ट्र' निर्माण और 'अखंड भारत' के सपने दिखाकर देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा कर रहा है। अफ़सोस तो यह कि इस मिशन में राजनेताओं,धर्मगुरुओं से लेकर टी वी चैनल्स तक के स्वामी व पत्रकार खुलकर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भूख,ग़रीबी और मंहगाई से जूझ रहे प्रकृतिक रूप से उदारवादी स्वभाव रखने वाले हिन्दू भाइयों को चार चार बच्चे पैदा करने,घरों में हथियार रखने,मुसलमानों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ने,मुसलमानों का व्यवसायिक बायकॉट करने,उनके धार्मिक व सामाजिक मामलों में दख़लअंदाज़ी कर उन्हें उत्तेजित करने व चिढ़ाने जैसे प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। और इस तरह की 'असंवैधानिक ' बातों पर अब देश के अनेक क्षेत्रों के लोग भी खुलकर अपनी नाराज़गी का इज़हार करने लगे हैं।

पिछले दिनों अंबाला में सांप्रदायिकता फैलाने के लिये बदनाम हो चुके एक टी वी चैनल के प्रमुख ने 'समान नागरिक संहिता ' पर परिचर्चा के नाम पर कुछ हिंदूवादियों की भीड़ इकट्ठी की। ज़ाहिर है इसमें इकट्ठे हुये अधिकांश लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,भाजपा,विश्व हिन्दू परिषद् तथा इससे जुड़े अन्य संगठनों के सदस्य ही थे। इस में अंबाला शहर के स्थानीय विधायक जो कि भाजपा के ही हैं उन्होंने भी शिरकत की। यह आयोजन चर्चा का विषय इसलिये बन गया कि उन्मादी बातें करने में माहिर टी वी चैनल प्रमुख ने इस आयोजन में मौजूद लोगों को हिन्दू राष्ट्र बनाने की एक शपथ दिलाई। इस शपथ की भाषा पूरी तरह उत्तेजनात्मक व ग़ैर संवैधानिक तो थी है साथ ही भारतीय संविधान के अंतर्गत विधान सभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले किसी विधायक के लिये तो बिल्कुल ही अनावश्यक व असंवैधानिक भी थी । टी वी प्रमुख व विधायक के साथ साथ शपथ लेने वाले सभी लोग अपने हाथ उठाकर कह रहे थे कि -'हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसे हिंदू राष्ट्र बनाए रखाने को प्रतिबद्ध हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे या आवश्यकता पड़ी तो लेंगे। लेकिन हम देश को किसी भी क़ीमत पर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमारे पूर्वज और ईश्वर हमें हमारा लक्ष्य पाने की शक्ति दें। इसके पश्चात् हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे लगाए गए जिसमें विधायक को भी सभागार में मौजूद अन्य लोगों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाते देखा गया।

ग़ौरतलब है कि जिस जगह यह आयोजन हो रहा था वह स्थान हरियाणा-पंजाब सीमा से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले अंबाला का पड़ोसी पंजाब का ज़िला पटियाला ख़ालिस्तान समर्थक व ख़ालिस्तान विरोधियों के बीच हुई झड़प का केंद्र बना था। उस घटना के अभी एक सप्ताह भी नहीं बीते थे कि टी वी प्रमुख के भेस में पूरे देश में बेलगाम घूमता फिर रहा यह व्यक्ति अंबाला आकर यहां का शांतिपूर्ण वातावरण 'प्रदूषित ' करने की पूरी कोशिश कर गया। उसके द्वारा दिलाई गयी हिन्दू राष्ट्र की शपथ व उसमें स्थानीय भाजपा विधायक की मौजूदगी के बाद अंबाला के सिख समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई। । शहर की कई संस्थाओं ने विधायक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहब में अनेक प्रमुख सिख नेताओं सहित अन्य सभी धर्मों के लोगों ने भी इकठ्ठा होकर इस आयोजन विशेषकर विधायक द्वारा हिन्दू राष्ट्र की शपथ लेने पर गहरा रोष जताया। सिख समाज द्वारा बुलाई गयी बैठक में कई वक्ताओं ने कहा कि विधायक का इस प्रकार शपथ लेना क़तई उचित नहीं है, यह भारत को तोड़ने वाला बयान है,हिन्दू राष्ट्र की मांग करना देशद्रोह है। उपस्थित लोगों ने विधायक के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करने की बात कही और कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो सिख समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अगली रणनीति तैयार करेगा। इसी सभा में जहां कुछ वक्ताओं ने हिन्दू राष्ट्र व ख़ालिस्तान दोनों के ही निर्माण की संकल्पना का विरोध करते हुये 'एक भारत-सशक्त भारत' की ज़रुरत पर ज़ोर दिया वहीं कुछ लोग यह कहने से भी नहीं चूके कि यदि हिन्दू राष्ट्र की मांग जायज़ है तो ख़ालिस्तान की मांग नाजायज़ क्यों है ?

केवल सिख समाज में ही नहीं बल्कि हिन्दू राष्ट्र की प्रतिध्वनि अब असम में भी सुनाई देने लगी है। पिछले दिनों असम के सिबसागर क्षेत्र के विधायक एवं प्रतिष्ठित आर टी आई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने असम में मूल असमी निवासियों की सामाजिक सुरक्षा के मद्देनज़र भारतीय संविधान की धारा 370,371(ॅ),371(इ) और 371(ठ) जैसे प्रावधानों को लागू करने की मांग की। गोगोई ने साफ़ तौर से यह कहा कि भाजपा,आर एस एस केवल हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा की संघ व भाजपा का एजेंडा देश की विविधता तथा भारतीय संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। एन आर सी व समान नागरिक संहिता को भी गोगोई ने अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक बताया। इसी प्रकार कश्मीर,गोवा व पूर्वोत्तर व दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में संघ व भाजपा के इस तरह के समाज विभाजक एजेंडे का विरोध किया जाता रहा है। परन्तु केवल सत्ता की चाहत में बहुसंख्यवाद की राजनीति को परवान चढ़ाने की अपनी कोशिशों में ये लोग यह भूल जाते हैं कि देश का विकास समस्त देशवासियों के संयुक्त प्रयासों व उनकी एकजुटता से ही संभव है। झूठ,फ़रेब,दक़ियानूसी सोच विचार और सहस्त्राब्दियों पीछे ले जाने की संकल्पना देश व समाज को विभाजित तो ज़रूर कर सकती है परन्तु आगे हरगिज़ नहीं ले जा सकती। हाँ इसके नाम पर देश में अशांति व अस्थिरता फैलाकर कुछ समय सत्ता की मौज ज़रूर लूटी जा जा सकती है। लिहाज़ा हिन्दू राष्ट्र के नाम पर समाज विभाजक एजेण्डा चलाना हरगिज़ मुनासिब नहीं। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिये जो भारतीय संविधानक की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर शोभायमान हों। (लेखक- तनवीर जाफ़री/ ईएमएस)

लाउडस्पीकर्स की आड़ में,बाकी सभी ज्वलंत मुद्दे भाड़ में

प्रकृत्ति के बदलते परिवेश में गोलोबल वार्मिग में प्रदुषण रूपी दानव नें ताड़व मचा रखाहै। प्रदुषण की श्रेणी में हवा प्रदुषण ' जल प्रदुषण,ध्वनि प्रदूषण है जो श्रृष्टि के विनाश के लिए जिम्मेदार है।समय समय पर प्रदुषण रूपी राक्षस को रोकने के लिए माननीय न्यायालय को दिशा निर्देश जारी करना पड़ता है।प्रदुषण के श्रेणी में ध्वनि प्रदुषण को लेकर चिन्ता व चिन्तन का दौर से सम्पूर्ण देश दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। आज मै आप के समक्ष सता के गलियारो में लाउडस्पीकर की गर्जना से उपन्न ध्वनि प्रदूर्षण के बारे चर्चा करने वाला है।ध्वनि प्रदुषण की गुंज उत्तर प्रदेश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी राजनीति ने तूल पकड़ लिया है।विगत दिनों भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल और तीनों नगर निगमों को पत्र लिखे जाने के बाद अब दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. आदेश गुप्ता ने अपने पत्र में मांग की है कि राजधानी दिल्ली में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर लगे लाउडस्पीकर को तुरंत हटाया जाए क्योकि लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और लोगों को परेशानी होती है।

दिल्ली में लाउडस्पीकर पर मचे विवाद को लेकर राजनीति ने तुल पकड़ लिया है।इसमें अब दिल्ली बीजेपी भी कूद गई है।बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर राजधानी में सभी धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर्स हटाने की कार्रवाई करने की मांग की गई है।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर के आधार दिल्ली सरकार बिना तुष्टीकरण के दिल्ली में सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटाने की कार्रवाई शुरू करे।

पूरे देश भर में इन दिनों धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है ।पहले उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र और दिल्ली में भी इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली के अंदर भी लाउडस्पीकर के मामले को लेकर सियासी दलों की खींचतान शुरू हो गई है।

लाउडस्पीकर्स को हटाने को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की पीसीइस सबके बीच मंगलवार सुबह दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूरे मामले पर मीडिया के सामने आकर बातचीत की। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ठवर्तमान समय में राजधानी दिल्ली के अंदर चाहे वह वायु प्रदूषण,जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण हो सब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है. जिस पर अब लगाम लगाना आवश्यक है. आज देश के कई राज्यों में ध्वनि प्रदूषण पर लाउडस्पीकर को लेकर न सिर्फ गंभीर चर्चा हो रही है बल्कि कुछ राज्यों में लाउडस्पीकर पर रोक भी लगा दी गई है।इस तरह के फैसले का नागरिकों ने भी स्वागत किया है।लाउडस्पीकर के शोर के चलते पढ़ने वाले छात्रों-छात्राओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं उसके तहत राज्य सरकारों को ही निर्धारित करना है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं।देश के अंदर बहुसंख्यक समाज ने लाउडस्पीकर्स पर रोक लगाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेने के साथ उसका समर्थन किया है।

लाउडस्पीकर्स हटाने की कार्रवाई शुरू करे।अगर लाउडस्पीकर्स बजाने भी हैं कोई तो उसके लिए प्रशासन से पहले इजाजत लेना अनिवार्य है।जब दुबई और इंडोनेशिया जैसे देशों में लाउडस्पीकर्स पर रोक लगा दी गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं लगाई जा सकती है।गुप्ता ने इस प्रकरण पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो आदेश जारी किये गए हैं उसमें संस्थानों, बैंक्विट हॉल और अन्य बंद जगहों पर लाउडस्पीकर बजाने के मद्देनजर समय को निर्धारित किया गया है,लेकिन मस्जिदों को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।दिल्ली सरकार तुष्टीकरण की नीति छोड़ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का करे।

कानून की नजर में लाउडस्पीकर्स का विरोध; सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर चुका है।माननीय न्यालाय के द्वारा जबरन ऊंची आवाज नागरिको के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

मौजूदा वक्त में मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स बजाने को लेकर उपजे विवाद ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है लेकिन इसके वैज्ञानिक और कानूनी पहलू भी हैं जिसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।

आप को बता दे कि ध्वनि प्रदूषण पर क्योो कहता है हमारा कानून ।

सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण पर रोक के मामले में दिए अपने फैसले में कह चुका है कि जबरदस्ती ऊंची आवाज यानी तेज शोर सुनने को मजबूर करना मौलिक अधिकार का दुसरे को भी शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लाउडस्पीकर्स या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है,लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती।

किसी को भी शोर करने का अधिकार नहीं है जिससे उसके घर से बाहर जाकर पड़ोसियों और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा करे। माननीय न्यायालय ने कहा था कि शोर करने वाले अक्सर अनुच्छेद 19(1)ए में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की शरण लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर चालू कर इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

हमारा संविधान अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास सुनने या सुनने से इन्कार करने काअधिकार है। लाउडस्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना दूसरों के शांति और आराम से प्रदूषणमुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद-21में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।अनुच्छेद 19(1)ए में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है।

एक अंहम फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज उस क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से 10 डेसिबल (ए) से ज्यादा नहीं होगी या फिर 75 डेसिबल (ए) से ज्यादा नहीं होगी, इनमें से जो भी कम होगा वही लागू माना जाएगा।जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो,वहां लाउडस्पीकर व उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रविधान करे।आप को बना दे कि ध्वनि के तय मानक है।न्यायलय केआदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कोर्ट स्वयं इसमें बदलाव न करे या इस बारे में कानून न बन जाए।ज्ञात्वय रहे कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने का मानक है। पर्यावरण संरक्षण कानून,1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और तय मानकों के उल्लंघन पर सजा के प्रविधान दिए गए हैं। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम, 2000 बने हैं जिनमें ध्वनि के मानक तय हैं। सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर्स के लिए पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है।

लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट,जानें क्यान है पूरा मामला विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह में रात 10 से 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने के लिए विशेष इजाजत की जरूरत होती है जो अधिकतम 15 दिन के लिए ही मिल सकती है और आवाज की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल हो सकती है।लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पेश होते रहे वरिष्ठ वकील विजय पंजवानी कहते हैं कि कानून में ध्वनि की सीमा उल्लंघन पर धारा 15 में सजा का प्रविधान है, लेकिन ये प्रभावी ढंग से लागू नही होती।नियम का उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है।लगातार उल्लंघन पर 5,000 रुपये रोज जुर्माने का प्रविधान है। ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस परिसर में घुसकर लाउडस्पीकर्स जब्त कर सकती है।

फिलहाल आप से यह कहते हुए विदा लेते है कि ठ ना ही काहुँ से दोस्ती ' ना ही काहूँ से बैर ।

खबरी लाल तो मांगे, सबकी खैर ?(लेखक-- विनोद तकिया वाला/ ईएमएस)

आज का इतिहास 11 मई

1812 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्पेंसर पर्सीबेल की हत्या हुई.
1824 ब्रिटेन ने रंगून पर कब्जा किया.
1878 जर्मनी के शासक विलियम प्रथम पर जानलेवा हमला हुआ.
1904 स्पेनी कलाकार सल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था.
1943 द्वितीय युद्ध में अमरीकी फौजे को एल्यूरिन द्वीप पर पहुंची.
1949 स्याम ने अपना नाम थाईलैंड रखा.
1951 सोमनाथ मंदिर जनता के लिए खोल दिया गया.
1971 इजरायल में एंगोरवाट के मंदिर ध्वस्त हुए.
1973 पश्चिम जर्मनी की संसद ने पूर्व जर्मनी से संबंध कायम करने को मंजूरी दी.
1991 सोवियत राष्ट्रपति गोर्वाचेव ने अपने देश में अराजकता व्याप्त होने की आशंका व्यक्त की.
1995 आतंकवादियों ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरूद्दीन वली की मजार चरारे शरीफ को आग लगाकर नष्ट किया.
1996 भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया.
1998 भारत ने राजस्थान के पोकरण में हायड्रोजन बम समेत तीन परमाणु परीक्षण करके आणविक क्षेत्र में महाशक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ाया.
1999 उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के 19 अभियुक्तों को रिहा किया व अन्य छः जनों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला.
2000 नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में प्रतीकात्मक एक अरबवे बच्ची आस्था का जन्म.
2004 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को तीन चौथाई बहुमत.

शब्द पहेली - 7282

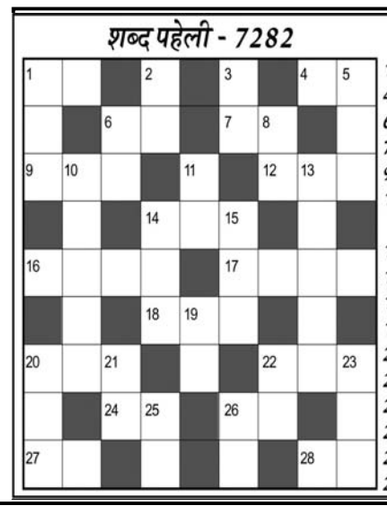

बाएँ से दाएँ

1.ध्वज,पताका-2
4.वहम,संदेह-2
6.दलहन-2
7.खाली,रिक्त-2
9.रसूल,अल्लाह-3
12.अभिनेत्री मुनमुन सेन की पुत्री का सिर्फ नाम-3
14.सिवाय,बगैर-3
16.इराक की राजधानी-4
17.समधी की पत्नी-4
18.पीसना,महीन करना-3
20.उष्ण,गर्म-3
22.उत्तम,विष्णु अवतार-3
24.परत,तह-2
26.खेती-2
27.अधर,होठ-2
28.ताऊ की पत्नी,बड़ी मां-2

ऊपर से नीचे

1.जल प्रपात-3
2.आईल-2
3.हूर,अप्सरा-2
5.सूक्ति,वाणी,शबद-3
6.पिता के पिता-2
8.स्टार,सितारा-2
10.रोचक,सुंदर,मनोहारी-5
11.शीतलता,मुठभेड़-2
13.सतरंगा,शंकर धनुष-5
14.सिर्फ एक,एकमात्र-3
15.हवस,कामेच्छा-3
19.लाख-2
20.जहर,विष-3
21.आनंदित,मनमौजी-2
22.मुनि,साधू-2
23.अच्छाई,सदशयता-3
25.सुरक्षा-2
26.कीड़ा,कीट-2

शब्द पहेली -7281 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पहली बार मुम्बई को मिली सबसे ज्यादा हार

मुंबई (ईएमएस)। आईपीएल के इस 15 वें सत्र में मुम्बई इंडियंस टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और वह अंकतालिका में सबसे नीचे है। कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के खिलाफ हार के साथ ही मुम्बई की टीम के नाम एक और अनचाहा रिकार्ड जुड़ गया है। मुंबई को आईपीएल के किसी एक सत्र में पहली बार इतनी ज्यादा हार मिली हैं। मुंबई इंडियंस को इससे पहले, 2009, 2014 और 2018 के सत्र में आठ-आठ मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2012, 2016 और 2021 के सत्र में उसे 7-7 मैचों में हार मिली थी।

प्लेऑफ में जगह बनाने आज आमने-सामने होंगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स

नवी मुंबई (ईएमएस)। दिल्ली कैपिटल्स की टीम बुधवार को आईपीएल के अपने एक अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला करेगी। दिल्ली की टीम का लक्ष्य किसी भी हाल में यह मैच जीतकर प्लेऑफ के लिए अपनी संभावनाएं बनाये रखना रहेगा। उसने अब तक 11 में से 6 मैच हारे हैं और इस प्रकार वह 10 लेकर अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। ऐसे में उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने तीनो ही मैच जीतने होंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की टीम की राह आसान नजर आती है। टीम 11 मैचों में 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है और उसे क्वालीफाई करने के लिये केवल दो मैच ही जीतने हैं। इस मैच को जीतते ही उसके गुजरात के बराबर 16 अंक हो जाएंगे और बेहतर रन औसत के आधार पर उसका प्लेऑफ में पहुंचना तय है।

अगर अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस मैच में राजस्थान की संभावनएं प्रबल हैं क्योंकि दिल्ली की टीम के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। उसके पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में कैपिटल्स के गेंदबाज भी प्रभावी नहीं रहे थे। केवल स्पिनर कुलदीप यादव ही दो विकेट ले प

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में यह गिरावट विदेशी निवेशकों की बिकवाली से घरेलू बाजारों पर पड़े दबाव के कारण आई है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 54,857.02 के ऊंचे स्तर और 54,226.33 के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद अंत में 105.82 अंक करीब 0.19 फीसदी के नुकसान से 54,364.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 61.80 अंक तकरीबन 0.38 फीसदी नीचे आकर 16,240.05 अंक तक खिसक गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील, सन फार्मा, एनटीपीसी, टाइटन, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा और आईटीसी के शेयर नीचे आये। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर लाभ में रहे हैं। शेयर बाजारों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने गत दिवस 3,361.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो हांगकांग का हैंगसेंग और द. कोरिया का कॉस्पी गिरावट के साथ बंद हुए जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त पर रहा , अमेरिकी शेयर बाजारों में भी गिरावट रही। दूसरी ओर यूरोप के शेयर बाजारों में मजबूती रही।

27.5-28.5 गीगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी रेंज की नीलामी पर दूरसंचार विभाग करेगा निर्णय : ट्राई

नयी दिल्ली (ईएमएस)। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि आईएमटी/5जी सेवाओं के लिए 27.5-28.5 गीगाहट्र्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज आवंटित या उसकी नीलामी करने के बारे में दूरसंचार विभाग को फैसला करना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3,300-3,670 मेगाहट्र्ज और 24.25-27.5 गीगाहट्र्ज बैंड के लिए निर्धारित अलग-अलग बैंड विशेष के लिए न्यूनतम रोलआउट दायित्वों पर अपने सिफारिशों का बचाव किया।

दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा न्यूनतम रोलआउट दायित्वों को 3,300-3,670 मेगाहट्र्ज बैंड और 24.25-27.5 गीगाहट्र्ज बैंड पर संयुक्त तरीके से लागू करने की बात कहने पर ट्राई ने तर्क दिया कि इन बैंडों की नीलामी एक साथ नहीं, बल्कि अलग से की जाएगी। ट्राई ने कहा कि इन दोनों बैंडों की तकनीकी विशेषताएं काफी अलग हैं और इन स्पेक्ट्रम बैंडों के उपयोग के मामले भी अलग होने की संभावना है।

इस साल कर्मचारियों के पीएफ खाते में जल्द आएगा ब्याज, आसानी से चेक किया जा सकेगा बैलेंस

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस साल अपने करोड़ों सब्सक्राइबर को बड़ा तोहफा दे सकता है। ईपीएफओ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस साल पीएफ खाते में ब्याज की रकम जल्दी आ जाएगी। दरअसल, देशभर के सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड ईपीएफओ के पास होता है, जो कर्मचारियों के वेतन से एक तय मात्रा में हर महीने कटौती करता है और रिटायरमेंट पर मोटी रकम के रूप में कर्मचारी को लौटा देता है।

इसके अलावा वेतन से काटी गई राशि के हिसाब से कर्मचारी को पेंशन भी ईपीएफओ की ओर से ही मिलती है। वेतन से कटने वाली राशि पर ईपीएफओ हर साल ब्याज देता है, जो उसका ट्रस्ट तय करता है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ब्याज का पैसा खाते में डाल दिया जाता है।

ईपीएफओ ट्रस्ट ने मार्च में हुई बैठक में वित्तवर्ष 2021-22 के लिए पीएफ खाते पर 8.10 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया है। फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस पर ज्यादा समीक्षा करने के बजाए जल्द मंजूरी दे देगा। दरअसल, इस बार दी जाने वाली ब्याज दर पिछले चार दशक में सबसे कम है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे कि ब्याज का पैसा इस साल जल्दी खाते में आ जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि इस साल दशहरा अथवा दिवाली तक ब्याज का पैसा सब्सक्राइबर के खाते में भेज दिया जाएगा। अमूमन इस ब्याज का पैसा आने में दिसंबर तक का समय लग जाता है।

इस साल फरवरी में ईपीएफओ अपने साथ 12.37 लाख नए खाते जोड़े हैं। अगर ईपीएफओ ब्याज का पैसा जल्दी देता है तो उसे ही फायदा होगा, क्योंकि अभी होने वाले सभी सेटलमेंट पिछले साल की ब्याज दर पर करना पड़ रहा, जो 8.5 फीसदी थी। ऐसे में नई ब्याज दर लागू होने के बाद ईपीएफओ को सेटलमेंट में कम ब्याज देना पड़ेगा।

32.91 रुपये हुई आटे की औसत कीमत, एक साल में एक किलो आटे में 4 रुपए से ज्यादा की वृद्धि

नई दिल्ली (ईएमएस)। एक आदमी एक दिन में कम से कम 4 रोटियां खाता है। हम कभी 4 रोटियों की कीमत का अनुमान नहीं लगाते क्योंकि हमारे घरों में औसतन एक माह का राशन एकसाथ आता है। कभी 4 रोटी का हिसाब लगाएं तो ये कितना होगा? इसका हिसाब लगाने के लिए कुछ अनुमान लगाना होगा। 4 रोटी बनाने में औसतन 100 ग्राम आटा लगता है। आज से 10 साल पहले एक किलो आटा 22.48 रुपए का आता था। इस हिसाब से 4 रोटी बनाने में 2.24 रुपये का आटा लगता था। वहीं, आज एक किलो आटा 32.91 रुपये का आ रहा है। लिहाजा 4 रोटी बनाने में 3.29 रुपये का खर्च आ रहा है। यानी, 10 साल में ही 4 रोटी की कीमत एक रुपये तक बढ़ गई है।

आटे की बात इसलिए, क्योंकि इसकी कीमत अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, 9 मई को देश में एक किलो आटे की औसत कीमत 32.91 रुपये रही। अकेले एक साल में ही एक किलो आटे की कीमत 4 रुपये से ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, देश में गेहूं का उत्पादन घट रहा है और स्टॉक भी कम हो रहा है। इसके अलावा, देश के बाहर गेहूं की डिमांड भी बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 मई को राजधानी दिल्ली में एक किलो आटे की कीमत 27 रुपए थी।

वहीं, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में 59 रुपये प्रति किलो आटा बिक रहा है। मुंबई में एक किलो आटा 49 रुपये में मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के पहले दिन से ही आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है। 1 जनवरी से अब तक आटे की कीमत 6 फीसदी तक बढ़ चुकी है। रूस और यूक्रेन जंग ने गेहूं के उत्पादन को और गिरा दिया है। दुनिया के गेहूं निर्यात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी एक चौथाई थी। सन 2019 में रूस ने 8.14 अरब डॉलर और यूक्रेन ने 3.11 अरब डॉलर का गेहूं निर्यात किया था।

इन दोनों देशों में युद्ध की वजह से दुनियाभर में गेहूं की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ रही हैं। भारत में गेहूं की कीमत बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारतीय गेहूं की बाहर बहुत ज्यादा डिमांड है, जिससे देश में कीमतें बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमत से गेहूं को लाने-ले जाने वाला खर्च भी बढ़ गया है।

सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि चावल-दाल, तेल और नमक की कीमत भी काफी बढ़ गई है। 10 साल में एक किलो चावल की कीमत 42 फीसदी तक बढ़ गई है। 9 मई 2013 को एक किलो चावल की औसत कीमत 25.40 रुपए थी, जो 9 मई 2022 को बढ़कर 36.07 रुपये हो गई है। इसी तरह तुअर दाल की कीमत में 48 फीसदी का उछाल आया है। एक किलो तुअर दाल की कीमत 10 साल में 70 रुपए से बढ़कर 102 रुपये के पार पहुंच गई है।

इसके अलावा तेल की कीमतें भी जमकर बढ़ी हैं। मूंगफली तेल 10 साल में 43 फीसदी तक महंगा हो गया है। सरसों के तेल की कीमत 84 फीसदी तक बढ़ी है। सबसे ज्यादा पाम ऑयल महंगा हुआ है। इसकी कीमत 10 साल में 140 फीसदी बढ़ गई है। जबकि, वनस्पति तेल 10 साल में 129 फीसदी महंगा हो गया है।

आटे की कीमत बढ़ने से बेकरी आइटम्स भी महंगे होने लगे हैं। हाल के कुछ महीनों में बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट और ब्रेड की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। बेकरी ब्रेड की खुदरा महंगाई इस साल मार्च में 8.39 फीसदी रही थी, जो 7 साल में सबसे ज्यादा है। जैम बिस्किट, मैरी गोल्ड जैसे बेकरी आइटम्स बनाने वाली ब्रिटानिया आने वाले समय में अपनी कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।

व्यापारियों की समस्याएं हल करने के लिए विकसित किया जाएगा एप : गर्ग

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं को हल करने और स्थाई समाधान पाने में मदद के लिए एक एप विकसित करने पर विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और, इस कड़ी में बोर्ड की एक एप विकसित करने की योजना है, जिसके माध्यम से व्यापारी अपेक्षाकृत कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। गर्ग ने बताया कि उन्होंने केंद्र से भी यह आग्रह किया है कि देश के सभी राज्यों में व्यापारी कल्याण बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए और उन्हें एक आयोग का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वे व्यापारियों को उनकी शिकायतों के निवारण में मदद कर सकें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में व्यापारी कल्याण बोर्ड हैं।

ईपीएफओ ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बनाया और आसान, पेंशनर्स को मिलेगी राहत

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर्स कभी भी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि वे जब भी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे तो वह उस तिथि से एक साल के लिए ही मान्य रहेगा।

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया कि ईपीएस'95 पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से एक साल के लिए वैध होगा। पेंशनर्स को बिना रुकावट अपनी पेंशन लेने के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होता है।

लाइफ सर्टिफिकेट से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पेंशनधारी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इसे जमा कराया जा सकता है।

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए पहली बार पेंशनधारकों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन में पेंशनर्स के आधार और बायोमेट्रिक के जरिए उसकी एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। यह आईडी बनने के बाद पेंशनर्स ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स यह आईडी बनने के बाद जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाकर डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं।

जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है। अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फेमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है, तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पूरी जिंदगी के लिए वैलिड नहीं है। वैलिडिटी पीरियड खत्म हो जाने के बाद नए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।

चीन के 300 अरब नहीं चुकाए तो पाक में होगा ब्लैकआउट

इस्लामाबाद(ईएमएस)। पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन की कंपनियों ने आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके पाकिस्तान को धमकी दी है कि यदि उसने बकाया 300 अरब रुपए नहीं चुकाये तो वह पकिस्तान की बिजली गुल कर देंगे। पाकिस्तान में काम कर रही दो दर्जन से अधिक चीनी फर्मों ने कहा कि उन्हें इस महीने अपने बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन चीनी कंपनियों का पाकिस्तान पर 300 अरब रुपये से अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका भुगतान अग्रिम तौर पर नहीं किया जाता है वे बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे।

30 चीनी कंपनियां बहु-अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत पाकिस्तान में काम करती हैं और पाकिस्तान के ऊर्जा, संचार, रेलवे सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में इनका दबदबा है। चीनी कंपनियों के साथ पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री अहसान इकबाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये विषय उठा तो पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं था। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने इस बैठक में जटिल वीजा प्रक्रियाओं, टैक्स आदि से संबंधित कई शिकायतें पाकिस्तानी मंत्री के सामने रखीं थी।

चीनी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के लगभग 25 प्रतिनिधियों ने एक के बाद एक पाक मंत्री से बात की। इस दौरान उन्होंने अपना बकाया भुगतान न चुकाए जाने को लेकर शिकायत की और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वे कुछ ही दिनों में बिजली संयत्रों को बंद कर देंगे। पाक अधिकारियों ने चीनी कंपनियों से गर्मी की चरम जरूरतों को देखते हुए उत्पादन को अधिकतम करने के लिए दबाव बनाया। इस पर चीनी कंपनियों ने कहा कि ठगंभीर पैसों की कमी को देखते हुए यह हमारे लिए यह असंभव हैठ

चीनी कंपनियों ने शिकायत की कि ईंधन की कीमतें, विशेष रूप से कोयले की कीमतों में तीन से चार गुना वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ईंधन की व्यवस्था करने के लिए कम से कम तीन से चार गुना अधिक पैसे दिए जाने चाहिए। कोयला उत्पादकों में से एक ने बताया कि कोयले के कम स्टॉक के कारण यह आधी क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों के दबाव से कुछ दिनों में ईंधन का स्टॉक समाप्त हो सकता है। उनमें से कुछ कंपनियों ने कहा कि पहले से आपूर्ति की जा चुकी बिजली का भुगतान अभी तक नहीं मिला है और वे कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों ने भी उन पर उच्च दरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। मंत्री इकबाल ने चीनियों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्थिति पर ध्यान दिया है और संबंधित अधिकारियों से उन्हें पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी देने और शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने के लिए कहा है। उन्होंने वादा किया कि चालू माह के भीतर उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर दिया जाएगा।

श्रीलंका- हिंसक झड़पों में अब तक 8 लोगों ने दम तोड़ा, महिंद्रा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग तेज हुई

कोलंबो (ईएमएस)। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर असफल श्रीलंका में इस समय बेहद हिंसक माहौल है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सरकार विरोधी और समर्थकों के बीच जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने 12 सांसदों के घरों को आग के हवाले कर दिया। अब महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। विपक्षी नेताओं ने महिंदा राजपक्षे पर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस हिंसा में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान कई राजनेताओं के घरों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं।

श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था, जिसके मद्देनजर पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया। महिंदा राजपक्षे द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल स्वतः ही भंग हो गया है और देश वर्तमान में उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा चलाया जा रहा है।

विपक्ष ने महिंदा राजपक्षे पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला करने के लिए सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उकसाने का आरोप लगाया है। प्रमुख तमिल सांसद एमए सुमनथिरन ने एक संदेश जारी कर कहा, 'महिंदा राजपक्षे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।' पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और मुख्य विपक्षी दल समागी जना बालवेग्या पार्टी के नेता रंजीत मद्दुमा बंडारा ने भी महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग की।

सिरिसेना ने कहा, ''महिंदा राजपक्षे को हिंसा को बढ़ावा देने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला करने का कोई कारण नहीं था।' महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद एक प्रदर्शनकारी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। महिंदा राजपक्षे ने अपने त्यागपत्र में कहा कि वह सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। यह फैसला छह मई को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में आपके अनुरोध के अनुरूप है, जिसमें आपने कहा था कि आप एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार का गठन चाहते हैं।'

महिंदा राजपक्षे ने कहा कि वह जनता के लिए 'कोई भी बलिदान' देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भी भंग कर दी गई। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर देश में जारी आर्थिक संकट से निपटने को अंतरिम सरकार बनाने का दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हंबनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक आवास में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं के घरों को भी आग के हवाले कर दिया।

पंजाब के बलविंदर सऊदी में बुरे फंसे, 6 दिन बाद सिर कर दिया जाएगा कलम

-पंजाब सीएम से मदद की गुहार

दुबई (ईएमएस)। खाड़ी देश सऊदी अरब के नियम-कानून दूसरे देशों से काफी भिन्न और कड़े हैं। वहां गलती की माफी नहीं होती। सऊदी अरब में पंजाब से वास्ता रखने वाले बलविंदर वहां के कानूनी दांव-पेंच में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें 6 दिन के भीतर 2 करोड़ रुपये चुकाने हैं या फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बलविंदर को बचाने की कोशिशों में लगे उनके परिवार ने अब पंजाब के सीएम भगवंत मान से मदद की गुहार लगाई है। बलविंदर सिंह के चचेरे भाई जोगिंदर सिंह ने बताया कि 2008 में मुक्तसर के गांव मल्लन के रहने वाले बलविंदर सिंह रोजगार के लिए सऊदी अरब चले गए थे। 2013 में एक एक्सीडेंट के दौरान किसी को चोट लग गई थी, बाद में उनकी मौत हो गई। इस मामले में बलविंदर को 7 साल की सजा हुई। सऊदी अरब में एक सजा पूरी करने के बाद परिवार से पूछा जाता है कि वो अपराधी के साथ क्या करना चाहते हैं।

पीड़ित परिवार ने 2 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो परिवार ने बलविंदर के लिए सिर कलम करने की सजा की मांग की है। 2019 से परिवार पैसे जुटा रहा है। अभी तक परिवार 1,20,00,000 रुपए जुटा पाया है। पहले जिस कंपनी में बलविंदर काम करते थे। उन्होंने वादा किया था कि वो मदद करेंगे लेकिन अब वो कोई मदद नहीं कर रहे। बलविंदर के परिवार वालों का आरोप है कि कंपनी ने ही उन्हें फंसाया है। जोगिंदर ने कहा कि बलविंदर के माता-पिता उनके इंतजार में मर गए। 32 साल के बलविंदर के बड़े भाई और बहन और गांव वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

फिलहाल परिवार आम लोगों से मदद की अपील कर रहा है। 2 करोड़ ब्लड मनी ना दी तो पंजाब के बलविंदर सिंह का सऊदी अरब में सिर कलम कर दिया जाएगा। बलविंदर के पास दो रास्ते हैं..या तो वे 'ब्लड मनी' की रकम चुकाएं..या फिर धर्म परिवर्तन करें, नहीं तो 15 मई के बाद उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। बलविंदर सिंह ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया है। बलविंदर सिंह के चचेरे भाई ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आगे आना चाहिए। भगवंत मान विदेशों में बसे पंजाबियों को वापस लाने की बात हमेशा करते हैं। मान को बलविंदर की वापसी के लिए मदद करनी चाहिए।

रूस बना रहा घातक शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल, पानी, हवा और जमीन से साध सकेगी निशाना

मॉस्को (ईएमएस)। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को ढाई महीने से अधिक हो गया है। यूक्रेन की सेनाएं रूसी सेना को पूरे मनोबल से पीछे धकेल रही है। इसी बीच रूस एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जिसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री ने की है। खबरों में बताया गया कि डिप्टी प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा है कि हथियारों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अमेरिका के हथियारों के भंडार के साथ बराबरी लाई जा सके। उन्होंने कहा, 'नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, जो हवा, जमीन और पानी से लॉन्च किए जा सकेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में इसके जरिए हम आगे निकल जाएंगे।' उन्होंने आगे कहा कि रूस आधुनिक विमानन प्रणालियों को नई मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, 'टीयू-22एम3एम मिसाइल कैरियर की टेस्टिंग हो रही है।' रूस के रक्षामंत्री सर्गेई शोइगु ने अगस्त 2021 में नई पीढ़ी के हाइपरसोनिक हथियारों के डेवलपमेंट की घोषणा की थी।

यूरी बोरिसोव ने कहा कि डेवलपमेंट के बाद हमारी मिसाइलों की रेंज बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, 'इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। अगर हम अभी के मिसाइल से तुलना करें तो ये बेहद सटीक रहेगा।' बता दें कि रूस ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की थी कि उसके पास पर्याप्त उच्च कोटि की सटीक क्षमता वाली मिसाइलें और गोला बारूद हैं। मार्च में पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि युद्ध में रूस के पास कोई भी सटीक गाइडेड मिसाइल नहीं है। रूस ने 9 मई को विक्ट्री डे मनाया। विक्ट्री डे परेड में रूस ने हथियारों का प्रदर्शन किया। इस परेड में यार्स अंतरमहाद्वीपीय थर्मोन्यक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये मिसाइल 12 हजार किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। मिसाइल का वजन 49.6 टन है जो 24500 किमी/घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। परेड में टी-90 टैंक और एस-400 मिसाइल का प्रदर्शन भी रूस ने किया।

जर्मनी और फ्रांस ने की रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की पेशकश, कहा बातचीत से ही निकलेगी राह

बर्लिन (ईएमएस)। फ्रांस और जर्मनी ने कीव और मास्को के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश करते हुए तुरंत युद्ध विराम की आपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच उभरे तनाव को कम करने और शांति स्थापित करने में वह मध्यस्थता करने को तैयार हैं। जबकि, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस की सेना की यूक्रेन से वापसी के लिए कदम उठाने की बात की है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले दोनों दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की शांति स्थापना को लेकर बात होनी भी बेहद जरूरी है। मैक्रों और ओलाफ ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही है। इन दोनों का ही कहना है कि इस युद्ध का हल केवल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों को ही बातचीत की मेज पर आना जरूरी है। इन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कर युद्ध को रोकना है। इसके लिए वे यूक्रेन की मदद बातचीत के लिए शर्तों और बिंदुओं को रखने में कर सकते हैं।

मैक्रों ने कहा वह जल्दी ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से एक नई यूरोपीयन कम्यूनिटी को बनाने के मुद्दे पर बात करेंगे। इस बारे में उन्होंने ओलाफ से भी बात की है।

इससे पहले मैक्रों ने कहा था कि यूक्रेन को यूरोपीयन यूनियर का सदस्य बनने में कुछ वर्षों से दशकों तक का समय लग सकता है। यह भी उसके यूरोपीयन यूनियन के अपने स्टैंडर्ड पर खरा उतरने के बाद का समय है। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की शुरुआत फरवरी के अंतिम दिनों में शुरू हुई थी।

यूक्रेन ने रूस के लिए पैदा किया संकट, इसीलिए किया हमला, जेलेंस्की बोले जल्द मनाएंगे दो विक्ट्री दिवस

मास्को (ईएमएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1945 में नाजी जर्मनी की हार में तत्कालीन सोवियत संघ की भूमिका रेखांकित करने वाले विजय दिवस के मौके का इस्तेमाल सोमवार को यूक्रेन में अपने युद्ध को एक बार फिर सही ठहराने के लिए किया। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की जीत की घोषणा नहीं की और यह संकेत भी नहीं दिया कि यह जंग किस दिशा में जा रही है। पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस की एक परेड का मुआयना किया जिसमें सैनिकों ने मार्च किया, सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया तथा बैंड बजाया गया। पुतिन के भाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि वह युद्ध की स्थिति से किस तरह निकलना चाहते हैं। उन्होंने इसके बजाय इन्हीं आरोपों को दोहराया कि यूक्रेन से रूस को खतरा है। पुतिन ने यूक्रेन समेत पूर्व की ओर नाटो के धीरे-धीरे बढ़ते कदमों पर अप्रसन्नता जताई है और यूक्रेन पर रूस के हमले को उचित ठहराने का प्रयास किया है।

यूक्रेन के नेताओं और उनके पश्चिमी समर्थकों ने अक्सर इन दावों का खंडन किया है कि कीव या नाटो से रूस को किसी तरह का खतरा है। यदि स्वीडन और फिनलैंड पश्चिमी देशों के गठबंधन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो तनाव और बढ़ सकता है। पुतिन ने सैनिकों के मार्च का निरीक्षण करते हुए कहा हर दिन खतरा बढ़ रहा है। रूस ने हमले को लेकर पहले ही कार्रवाई की है। यह बाध्यकारी, समय पर और एकमात्र सुधारात्मक फैसला था।

उन्होंने डोनबास के लिए चल रहे मौजूदा संघर्ष को रूस की ऐतिहासिक जमीन पर लड़ाई करार दिया। पूरे यूक्रेन और उसकी राजधानी पर कब्जे में शुरुआती विफलता के बाद रूस ने अपना ध्यान डोनबास पर केंद्रित कर रखा है। उस क्षेत्र में भी प्रगति थोड़ी धीमी है। कई विश्लेषकों ने पहले अनुमान व्यक्त किया था कि पुतिन अपने भाषण में किसी तरह की सीमित विजय की, खासतौर पर मारियुपोल में जीत की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन युद्ध की स्थिति से निकलना चाहते हैं जिसके कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं और उसके संसाधनों को लेकर स्थिति चिंताजनक हो गई है। पुतिन ने आज जब मॉस्को में विजय दिवस के मौके पर अपने दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी तो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर सायरन की आवाज गूंजी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने विजय दिवस संबोधन में कहा कि उनका देश अंततः रूस को हरा देगा। उन्होंने एक वीडियो में कहा बहुत ही जल्द यूक्रेन में दो विजय दिवस मनाए जाया करेंगे। हम कभी किसी के विरुद्ध नहीं लड़े। हम हमेशा अपने लिए लड़ते हैं। हम अपने बच्चों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हम जीतेंगे।

एलन मस्क को ताजमहल लुभाया, बताया 'असली अजूबा'

-दर्शन के लिए दादा-दादी ने बनाया था कीर्तिमान

वॉशिंगटन (ईएमएस)। विश्व के धनाढ्य शख्स एलन मस्क को प्रेम का प्रतीक ताजमहल ऐसा भा गया है। एलन मस्क ने इसे 'वास्तव में दुनिया का आश्चर्य' बताते हुए अपनी भारत की यात्रा को साझा किया। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह आश्चर्यजनक है। मैंने 2007 में दौरा किया और ताजमहल भी देखा, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है।' एलन मस्क अपनी यात्रा के बारे में बता ही रहे थे कि उनकी मां ने मस्क के दादा-दादी की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हवाई जहाज से ताजमहल तक वह जिस तरह से पहुंचे वह एक रेकॉर्ड है। एलन मस्क की मां मायो म

भाजपा सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा- दो अलग अलग भारत बना रही है

दाहोद (ईएमएस) आगामी छह महीने में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले गुजरात में राष्ट्रीय नेताओं का आवागमन शुरू हो गया हैं अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्र दाहोद में बड़ी रैली की थी मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उसी दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली का आगाज किया और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी समेत भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम गुजरात में किया था वही काम आज वे भारत में कर रहे हैं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमीरों के लिए एक अलग भारत और गरीबों के लिए एक अलग भारत का निर्माण कर रहे हैं देश में जिन संसाधनों पर गरीबों का हक है, भाजपा राज में उन्हें कुछ अमीर लोगों को दिया जा रहा हैं भाजपा शासित राज्य सरकार ने आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया हैं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आपको कुछ नहीं देगी, बल्कि आपसे सब कुछ ले लेगी आपको अपने अधिकार छीनने होंगे, तभी वह सब कुछ मिलेगा जिस पर आपका अधिकार हैं कांग्रेस दो नहीं बल्कि एक भारत चाहती है, जिसमें सभी लोगों का आदर सम्मान हो सभी स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तब मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का उपहास उड़ाया थी साथ ही कहा था कि मैं उसे रद्द करना चाहता हूं, परंतु करूंगा नहीं ताकि जनता याद करे कि कांग्रेस क्या किया था? उन्होंने कहा कि कोविड के समय जिन लोगों के काम नहीं था उस वक्त उन्हें गांवों में मनरेगा के जरिए रोजगार मिला थी अगर मनरेगा नहीं होती तो देश की स्थिति क्या होती यह आप कल्पना कर सकते हैं राहुल गांधी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों की नहीं बल्कि आदिवासी, गरीब, कमजोर समेत भारत के सभी लोगों की हैं दुर्भाग्य है कि इसका वंचित लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रही कांग्रेस सरकार ने अपने शासन में पूरा प्रयास किया था कि भारत का जो धन है, जल, जंगल और जमीन उसका फायदा देश के सामान्य नागरिकों को मिले और उसके लिए कई काम भी किए थे कांग्रेस सांसद ने कहा कि टीवी पर कोई गरीब, किसान या आदिवासी नजर नहीं आता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दिखते हैं 24 घंटे सिर्फ उनका चेहरा ही दिखाया जाता हैं उन्होंने कहा कि रोजगार की बात तो छोड़िए, गुजरात में भाजपा सरकार सरकारी कॉलेजों को बंद करके निजी खिलाडियों को सौंप रही हैं गुजरात की हर ईंट में आदिवासी का खून-पसीना हैं आपने गुजरात की सड़कें, इमारतें, बुनियादी ढांचा बनाया है, लेकिन आपको क्या मिला? कांग्रेस के सत्ता में आने पर तापी नदी लिंक परियोजना को रोकने का वादा करते हुए राहुल ने कहा कि वे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करेंगे, जिसे उन्होंने निजी खिलाड़ियों को नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम आपको आपके वे सभी अधिकार वापस दे देंगे जो गुजरात भाजपा सरकार ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खुश करने के लिए आपसे छीन लिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है या जेल जाना पड़ता है। क्या यह लोकतंत्र है? भाजपा सरकार आपको कुछ नहीं देने जा रही है। भाजपा आपका भविष्य 2-3 उद्योगपतियों को बेचने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया की भी आलोचना की और कहा कि वे हमें मोदी की तस्वीरें, बॉलीवुड हीरो की तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी वास्तविकता अलग है। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी थाली, लाईट की बात करते हैं तब मीडिया उनसे को सवाल नहीं करता कि गुजरात में 3 लाख लोगों की मौत हुई हैं गंगा लाशों से पट गई थी भारत में 50-60 लोगों की मौत हो गई और वह कहते हैं कि थाली बजाएं और लाईट चालू करो

राहुल गांधी ने कोविड महामारी से नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा, ''ये लोग (भाजपा) नहीं बताते कि कोरोना महामारी के समय मां गंगा लाशों से भर गईं। ये नहीं बताते कि कोरोना वायरस के संक्रमण से 50-60 लाख लोगों की मौत हो गई। सिर्फ यह कहा गया कि थाली बजाओ, लाइट जलाओ।'' उन्होंने कहा, ''हमारी कोशिश होगी कि आदिवासियों की आवाज को इतना मजबूत बनाएं कि देश के प्रधानमंत्री को यह आवाज सुनाई दे जाए। गुजरात में आंदोलन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। आंदोलन करने के लिए जिग्नेश मेवानी (विधायक) को तीन महीने की जेल की सुना दी गई। मुझे पता है कि जिग्नेश को 10 साल की सजा दे दो, तो भी वह डरने वाला नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''गुजरात के युवाओं से कहना चाहता हूं कि नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, लेकिन भाजपा के लोग यह नहीं देने वाले हैं।''

राहुल गांधी ने सूत की माला पहनने से किया इंकार, भाजपा ने कहा-सूत की माला परहेज क्यों?

वडोदरा (ईएमएस) गुजरात दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूत की माला पहनने से इंकार कर दिया भाजपा नेता ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया और ट्वीटर के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी सूत की माला पहनने से इंकार करते हैं भाजपा नेता ने सवाल भी किया है कि आखिर सूत की माला से इतना परहेज क्यों? मंगलवार को गुजरात दौरे पर आए राहुल गांधी के वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया जहां कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को सूत की माला पहनाने की कोशिश की लेकिन राहुल गांधी ने सूत की माला पहनने से इंकार कर दिया एयरपोर्ट के बाद वडोदरा सर्किट हाउस में विधायकों के साथ बैठक में राहुल गांधी के हाथ में सूरत की माला थी बैठक के बाद राहुल गांधी जब सीढियों से उतर रहे थे उस वक्त जैसे किसी बेकार चीज को रख देते हों और इस प्रकार सीढियों के रेलिंग पर सूत की माला रखी और आगे बढ़ गए घटना का वीडियो सामने आते ही वडोदरा भाजपा के नेता अशोक डांगर ने इसे हाथों हाथ उठा लिया और ट्वीट कर सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी को सूत की माला से इतना परहेज क्यों है? साथ ही लिखा कि गांधी की सरनेम धारण कर जिस परिवार ने वर्षों तक देश पर राज किया उस परिवार को गुजरात में आकर सूरत की माला पहनने में तकलीफ क्या है?

श्री बालकृष्ण दोशी को 'रॉयल गोल्ड मेडल 2022' से सम्मानित किया गया

-- अहमदाबाद स्थित प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट श्रीमान दोशी उन प्रतिभावान विरल व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें अपने जीवन में रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है

अहमदाबाद : जाने माने आर्किटेक्ट(शिल्पकार, वास्तुकलाविद्) बालकृष्ण दोशी ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित एक और पुरस्कार हासिल कर देश को गौरवान्तित किया है। उन्हें मंगलवार को प्रतिष्ठित ठरॉयल गोल्ड मेडल 2022ठ से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। उन्होंने अहमदाबाद में अनेक प्रतिष्ठित स्ट्रक्टचर(संरचनाओं) को डिजाइन किया है, जो काबिले तारीफ है एवं इसकी दुनियाभर में सराहना की जाती है।

श्री दोशी(94) भारत के एकमात्र और विश्व स्तर पर उन प्रतिभावान व्यक्तियों में शामिल है, जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है, जिसे आर्किटेक्चर(वास्तुकला) का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। श्री दोशी को 2021 में बोस्टन आर्किटेक्चरल कॉलेज, ळएँ सहित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा तीन मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। उन्हें पेरिस स्थित घ्ढ्ढरूढ्ढ ईंईंमि ्म्प्रूाूलि द्वारा `Global Award for Lifetime Achievement

for Sustainable Architecture' से भी नवाजा गया है।

जीवन भर के कार्य को मान्यता देते हुए 'रॉयल गोल्ड मेडल' व्यक्तिगत रूप से रानी एलिजाबेथ द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की प्रगति एवं विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

श्री दोशी ने कहा कि, मैं इंग्लैंड की रानी से रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए गौरवान्तित अनुभव कर रहा हूं। यह वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जब मुझे रॉयल गोल्ड मेडल मिलने की खबर मिली तो इसने 1953 में ले कॉर्बूसियर के साथ काम करने के मेरे समय की यादें ताजा कर दीं। यह सम्मान प्राप्त करने पर उनका उत्साह मुझे स्पष्ट रूप से याद है। आज छह दशक बाद, मैं अपने गुरु ले कॉर्बूसियर के समान पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए वास्तव में अभिभूत महसूस कर रहा हूं - मैं मेरे छह दशकों के अभ्यास के लिए सम्मान अनुभव कर रहा हूं। मैं अपनी पत्नी, अपनी बेटियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मेरी टीम और सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे स्टूडियो संगाथ में मेरे साथ में हैं।

रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट का चयन करने वाली 2022 ऑनर्स कमेटी की अध्यक्षता दी रॉयल इंस्टीटयूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स **(RIBA)** के अध्यक्ष साइमन ऑलफोर्ड ने की थी और इसमें आर्किटेक्ट एलिसन ब्रूक्स और पिछले साल के रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता सर डेविड एडजय **OBE,** आर्किटेक्ट और अकादमिक केट चेन और सांस्कृतिक इतिहासकार और संग्रहालय निदेशक डॉ गस केस्ली-हेफोर्ड ईंशामिल थे।

RIBA के अध्यक्ष साइमन ऑलफोर्ड ने कहा कि, 2022 के रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में बालकृष्ण दोशी को चुनने में समिति की अध्यक्षता करना एक सम्मान और प्रसन्नता की बात थी। 94 साल की उम्र में उन्होंने अपने आनंदमय उद्देश्यपूर्ण वास्तुकला के माध्यम से वास्तुकारों की पीढियों को प्रभावित किया है। ले कॉर्बूसियर के कार्यालय में बिताए उनके समय से प्रभावित रहे, फिर भी उनका कार्य एक मूल और स्वतंत्र विचारक का है। आर्किटेक्चर की कला, निर्माण के शिल्प और शहरी डिजाइन के अभ्यास में उनका उत्कृष्ट योगदान उन्हें इस पुरस्कार के लिए सबसे योग्य प्राप्तकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज ने आईपीओ के जरिए एंकर निवेशकों से 159 करोड़ रुपये जुटाए

खुदरा संपत्ति प्रबंधन फर्म, प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज ने सोमवार को कहा कि उसने अपने आईपीओ बिक्री से पूर्व एंकर निवेशकों से 159 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

बीएसई पर अपलोड किए गए सर्कुलर के अनुसार, कंपनी ने एंकर निवेशकों को 630 रुपये प्रति शेयर पर कुल 25,30,651 इक्विटी शेयर आवंटित करने का फैसला किया है, जिसकी कुल राशि 159.43 करोड़ रुपये है।

एंकर निवेशकों में सोसाइटी जेनरल, कुबेर इंडिया फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड (एमएफ), एचडीएफसी एमएफ, एक्सिस एमएफ, एलएंडटी एमएफ, यूटीआई एमएफ, केनरा रोबेको एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ, कोटक एमएफ और एचएसबीसी एमएफ शामिल हैं।

85,49,340 इक्विटी शेयरों की प्रारंभिक शेयर बिक्री में वैगनर लिमिटेड के 82,81,340 इक्विटी शेयर और शिरीष पटेल के 2,68,000 इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल है।

निवेशक कम से कम 23 इक्विटी शेयरों और उसके बाद इसके गुणकों में बोली लगा सकते हैं।

आबादी बढाने के लिए जैन समाज का अनोखा अभियान, दूसरी-तीसरी संतान पर मिलेंगे 10 लाख

कच्छ (ईएमएस) जैन समाज की लगातार घटती आबादी को देखते हुए समाज ने अनोखा अभियान शुरू किया हैं जैन समाज की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 'हम दो, हमारे दो-तीन' का नारा दिया गया हैं साथ ही दूसरी और तीसरी संतान पर दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 10 लाख देने ऐलान किया हैं कच्छ की मुंद्रा तहसील के बारोई गांव में कच्छ विसा ओसवाल जैन समाज की ओर यह घोषणा की गई हैं भारत में पारसी समाज ऐसा ही जिसकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही हैं पारसी समाज अपनी आबादी बरकरार रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा हैं पारसी समाज के बाद अन्य समाज भी जागृत हुए हैं और वह अपनी घटती जनसंख्या को लेकर चिंतित हैं जैन समाज भी घटती आबादी के चलते अब जागृत हुआ है और जनसंख्या बढ़ाने के लिए अनोखी घोषणा की हैं जैन समाज ने 'हम दो, हमारे दो-तीन' नारे के साथ ही नकद पुरस्कार की भी घोषणा की हैं ताकि जैन समाज का प्रत्येक परिवार दूसरी और तीसरी संतान पर विचार करे समाज की ओर से परिवार में जन्म लेने वाली तीसरी संतान के लिए सहायता दी जाएगी योजना के तहत समाज में दूसरी और तीसरी संतान के बाद एक लाख और प्रत्येक जन्म दिन पर रु. 50000 समेत कुल 18 वर्ष तक रु. 1000000 की सहायता दी जाएगी इस योजना का लाभ 1 जनवरी 2023 के बाद जन्म लेने वाली संतानों को मिलेगा समाज के लोगों ने भी इस योजना का स्वागत किया हैं जैन समाज के प्रमुख डॉ. कल्याणभाई केनिया के मुताबिक अपने कैरियर के पीछे पागल आज की पीढ़ी संयुक्त परिवार की भावना भूल गई हैं इसी वजह से हमने यह योजना बनाई है, ताकि परिवार बढ़े हमारे समाज के ज्यादातर लोग मुंबई में स्थायी हो गए हैं एक सर्वे में पता चला कि हमारे समाज के 400 घर हैं और उसमें 800 लोग कम हुए हैं अगर समाज की जनसंख्या बढ़ानी होगी तो प्रोत्साहन राशि ही एक विकल्प हैं इस योजना के लिए आवश्यक फंड समाज के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से एकत्र करने का फैसला किया गया है और सभी ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया हैं

मैं कांग्रेस में हूं, नरेश पटेल को राजनीति में शामिल होने पर जल्द फैसला करना चाहिए : हार्दिक

दाहोद (ईएमएस) गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख हार्दिक पटेल पार्टी से नाराजगी और पाटीदार नेता व खोडलधाम ट्रस्ट के प्रमुख नरेश पटेल को लेकर बयान दिया हैं हार्दिक पटेल ने कहा कि वह कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी रहेंगे हार्दिक पटेल ने कहा कि राजनीति में आने पर नरेश पटेल को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, ताकि गुजरात की जनता में असमंजस की स्थिति खत्म हो दाहोद में राहुल गांधी की उपस्थिति में आयोजित आदिवासी रैली में पहुंचे हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं चाहता हूं नरेश पटेल के मामले का जल्द से जल्द निराकरण हो नरेश पटेल को बार बार दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमांड के साथ बैठकें करनी पड़ रही हैं बीते दिन कांग्रेस के अन्य विधायक भी नरेश पटेल के साथ दिल्ली गए थे यह अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में फैसला करने में जितना विलंब होगा उतनी ही गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ेगी इसलिए नरेश पटेल को भी जल्द फैसला करना चाहिए दो महीने पहले नरेश पटेल के राजनीति में आने की चर्चा से गुजरात के लोगों में उत्साह हैं बीते दिन नरेश पटेल की दिल्ली यात्रा से नई उम्मीद पैदा हुई हैं हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूं राहुल गांधी गुजरात दौरे पर आए हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कांग्रेस से नाराजगी की चर्चा और भाजपा नेताओं से बढ़ती निकटता को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी में अपनी भूमिका निभा रहा हूं और मेरी नाराजगी जल्द समाधान भी होगी मैं कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख से कहीं ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और आज भी राहुल गांधी के साथ चर्चा जरूर करूंगी उन्होंने कहा कि आदिवासी सत्याग्रह सम्मेलन आदिवासियों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस का एक प्रयास हैं यह वही कांग्रेस ने जिसने गुजरात राज्य को पहला मुख्यमंत्री दिया थी कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ रही है और आदिवासी समाज भी कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा हैं आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार कांग्रेस ने दिया थी बता दें कि सोमवार को नरेश पटेल को दिल्ली ले गए कांग्रेस विधायक प्रताप दूधात, किरीट पटेल, ललित वसोया और ललित कथगरा बीती शाम ही लौट आए थे वडोदरा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में प्रताप दूधात ने कहा था कि पार्टी हाईकमांड के साथ नरेश पटेल की सकारात्मक बैठक हुई है और जल्द ही नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होंगे हांलाकि आज गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि अगले कुछ दिनों में चित्र स्पष्ट हो जाएगा जो कुछ भी चर्चा हो रही है उसका नतीजा भी आएगा इस संदर्भ में फिलहाल इस पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं हैं

गुजराती लोकगायिका काजल महेरीया पर हमला

पाटण, १० मई ।

गुजरात की लोकप्रिय गीतकार काजल महेरीया पर सोमवार की रात के दौरान हमला होने की घटना सामने आई है। पाटण के धारपुर गांव में संगीत के एक कार्यक्रम के दौरान काजल महेरीया पर हमला किया गया था। कई शख्सों ने कार्यक्रम के दौरान काजल महेरीया पर हमला करके लूट चलाई थी। सोने की चेन सहित की कई वस्तुओं की लूट की गई है।

जिसमें काजल महेरीया को मामूली चोटें आई है। जिसके बाद काजल को पाटण धारपुर की अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराई गई। इस पूरे मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। हमले के बाद काजल महेरीया ने पाटण के बालीसणा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें रमू देसाई नाम के शख्स सहित अन्य ४ शख्सों के खिलाफ हमले की शिकायत की है।

दिगडी गांव के रमू देसाई ने काजल पर पुरानी दुश्मनी को ध्यान में रखकर हमला किए जाने का कहा जा रहा है। इस हमले में काजल महेरीया को मामूली चोटें आई हैं। इसके साथ ही उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। वर्ष २०२० में सितंबर महीने में काजल महेरीया पर आंतरिक झगड़े में हमला हुआ था।

मोढेरा में बने यह मामले में काजल महेरीया को थप्पड़ मारा था।

पश्चिम रेलवे के नौ कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) प्रकाश बुटानी ने पश्चिम रेलवे के सभी छह मंडलों के 9 कर्मचारियों को ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट डयूटी निभाने के लिए सम्मानित किया। इन कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल, 2022 के महीनों के दौरान डयूटी में उनकी सतर्कता और अप्रिय घटनाओं को रोकने में उनके योगदान की सराहना के तौर पर तथा सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया। 9 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारी रतलाम मंडल से, 2 कर्मचारी अहमदाबाद मंडल से और 1-1 कर्मचारी मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, राजकोट और भावनगर मंडल से थे। इस बैठक में विभिन्नच विभागों के प्रमुख विभागाध्यटक्षों (इ्प्रेऊे) ने भाग लिया, जबकि सभी मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बुटानी ने सम्मानित किए जा रहे कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना की और उल्लेख किया कि उनका कार्य अन्य। के लिए अनुकरणीय है। सम्मानित किए गए कर्मचारियों ने संरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ब्रेक बाइंडिंग, पिनियन जैम, हॉट एक्सरल का पता लगाना, रेल एवं ट्रैक फ्रैक्चर का पता लगाना, चलती ट्रेन से टूटे एवं लटकते हुए पार्ट्स, वैगनों में फ्लैट टायर और रेलवे ट्रैक पर फंसे एक चार पहिया वाहन के बारे में सूचना देने आदि जैसे संरक्षा से संबंधित कार्यों को करते हुए ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने में उत्साह और प्रतिबद्धता दिखाई। रेलवे को उन सभी पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों पर गर्व है जिन्होंने अपनी त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को टालने में मदद की।

प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में कंथारपुर वड का यात्रा-पर्यटन धाम के रूप में सर्वग्राही विकास होगा : मुख्यमंत्री

- भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के निकट स्थित कंथारपुर महाकाली वड के यात्रा-पर्यटन धाम विकास प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का निरीक्षण किया

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के निकट दहेगाम तहसील के कंथारपुर महाकाली वड (बरगद) के यात्रा-पर्यटन धाम विकास प्रोजेक्ट के विभिन्न कामकाजों का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को स्वयं कंथारपुर वड पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के दिशादर्शन में गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा इस कंथारपुर महाकाली वड का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रा-पर्यटन धाम के रूप में विकास किया जा रहा है। गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण के विकास कार्य शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत इस स्थान पर नयनरम्य लैण्डस्कैपिंग, ध्यान-योग स्थानों, एग्ज़ीबिशन हॉल, पाथ-वे, गैदरिंग एरिया, पानी के बोरवेल, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से जुड़े कामकाज शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार सुबह राज्य के मुख्य सचिव पंकज कुमार, पर्यटन सचिव हारित शुक्ल, गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के सचिव आर. आर. रावल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राम कुमार, गांधीनगर ज़िला कलेक्टर कुलदीप आर्य एवं अधिकारियों के साथ कंथारपुर महाकाली वड पहुँचे। उन्होंने निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का विवरण प्राप्त किया तथा साइट निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव भी दिए। उन्होंने स्थानीय अग्रणियों एवं ग्रामीणजनों के साथ सहज संवाद किया। वे बच्चों के साथ भी स्नेह-भाव से मिले। भूपेंद्र पटेल ने इस परिसर में यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा पहले चरण में समग्रतः अनुमानित 14.69 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य किए जाने वाले हैं, उन्हें निश्चित समयावधि में और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि कंथारपुर वड (बरगद) 500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसे मिनी कबीर वड के रूप में जाना जाता है। कंथारपुर वड के नीचे महाकाली माता का मंदिर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालू इस मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। इतना ही नहीं, आधा एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस महाकाय बरगद की जड़ें भी प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस स्थान का दौरा कर इसे यात्रा-पर्यटन धाम के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में मोदी के इस संकल्प को साकार करने वाले यात्राधाम विकास के कार्य यहाँ तेज़ी से शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दौरे के दौरान प्रोजेक्ट के विकास कार्यों की गहराई से जानकारी ली।

इस महीने फिर गुजरात जाएंगे अमित शाह

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह इस महीने एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वह देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, केढ़ा और गोधरा जा सकते हैं। इसके अलावा वह कुछ मीटिंगों में भी शामिल होंगे, जिसमें चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों का जायजा लेंगे। यही नहीं कई कल्याणकारी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इस दौरान वह उद्घाटन भी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा उन सीटों पर फोकस करने की तैयारी में है, जहां अब तक उसे जीत नहीं मिल सकी है। ये सीटें दलितों और आदिवासी समुदायों की बहुलता वाली हैं, जिन्हें भाजपा का परंपरागत वोटर नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार भाजपा इन इलाकों में भी आक्रामक है। इसकी वजह यह है कि पार्टी का विचार है कि यदि उसे शहरी इलाकों में कोई झटका लगता है तो उसकी भरपाई यहां से हो सकेगी। इसी रणनीति के तहत उसने कांग्रेस के कई आदिवासी नेताओं को पार्टी में एंट्री दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाले गुजरात में भाजपा 99 सीटों पर ही ठहर गई थी। तब कांग्रेस को लेकर यह माना गया था कि उसने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। अब भाजपा का कहना है कि वह इस बार डबल डिजिट में नहीं रहना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का कहना है कि हमारी कोशिश है कि सभी 182 सीटों पर जीत के लिहाज से तैयारी की जाए। इसके लिए भाजपा ने बूथ लेवल पर ही तैयारी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जा रहा है। पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा उन सीटों पर फोकस कर रही है, जहां वह कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा, 'ऐसी करीब 30 सीटें हैं, जहां अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इस बार इन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है।

गांधीनगर के गियोड गांव में स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने लगाई चाय की चुस्की

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने मृदुभाषी, परंतु दृढ़ नेतृत्त्व के साथ-साथ अपनी सादगी और सहजता के लिए लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी इसी सादगी और सहजता का अनुभव गांधीनगर ज़िले के गियोड के ग्रामजनों को मंगलवार सुबह हुआ, जब मुख्यमंत्री अचानक गियोड पहुँच गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किसी भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा गाँव में किसी को बिना बताए ही गियोड गाँव पहुँचे। उन्होंने गियोड पहुँचकर यहाँ के वृद्धजनों से गाँव में सफ़ाई व्यवस्था, स्कूली शिक्षा आदि के बारे में पूछताछ की। भूपेंद्र पटेल ने गियोड गाँव के बच्चों के बीच पहुँचे। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ प्रेमपूर्वक संवाद कर भूपेंद्र 'दादा' के रूप में अपनी छवि को और उज्ज्वल बनाया। मुख्यमंत्री ने गाँव की माताओं-बहनों से भी भेंट की। उन्होंने ग्रामजनों के साथ बातचीत करते हुए चाय की चुस्की लगाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार सुबह कंथारपुर महाकाली वड (बरगद) के यात्रा-पर्यटन धाम के रूप में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुँचे थे। उन्होंने कंथारपुर वड से लौटते समय अचानक ही अपने सुरक्षा अधिकारियों के क़ाफ़िले को गियोड गाँव में ले जाने का निर्देश दिया तथा कोई भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बिना सीधे गियोड पहुँचे। गियोड के ग्रामजन मुख्यमंत्री को अपने गाँव में आते देखकर सुखद आश्चर्यचकित रह गए। इस भेंट में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव पंकज कुमार, गांधीनगर ज़िला कलेक्टर कुलदीप आर्य आदि भी शामिल हुए।

हार्दिक पटेल को राहत

सेशंस कोर्ट ने केस वापस लेने की याचिका मंजूर की

अहमदाबाद, १० मई ।

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज केस पर बड़ी खबर सामने आई है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद हुए विभिन्न केसों को वापस लेने के संदर्भ में राज्य सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी ।

हार्दिक पटेल एवं अन्य के खिलाफ रामोल थाने में दर्ज केस को वापस लेने के संदर्भ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को सेंशस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले २५ अप्रैल को केस वापस लेने की सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हार्दिक समेत २१ आरोपियों को कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। हार्दिक के खिलाफ अब राजद्रोह का केस ही लंबित है। अब पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान कुल ४८५ पुलिस केस दर्ज हुए थे। इसमें २२८ केस रद्द हो गए हैं, जबकि १४० केस पेंडिंग हैं। वर्ष २०१५ में पाटीदार आंदोलन के दौरान १४ पाटीदार युवकों की मौत हो गई थी। पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण कोटे में शामिल करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबहन पर दबाव बढ़ गया था। २० मार्च २०१७ को पार्षद परेश पटेल ने हार्दिक पटेल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वस्त्राल के तत्कालीन पार्षद परेश पटेल के घर आस्था बंग्लोज पर भीड़ ने हमला कर दिया था। सरकार ने इस केस को वापस लेने के लिए रिवीजन याचिका दायर की थी। आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज ९०० केसों में अभी १८७ केस पेंडिंग हैं। राज्य सरकार ने एक माह पहले १० केस वापस लेने का निर्णय लिया था।